

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1410

दिनांक 09 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत के निर्यात संबंधी निष्पादन में कमी

1410. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री संजय दिना पाटील:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार भारत के प्रमुख क्षेत्रों और वस्तुओं में हाल ही में निर्यात प्रदर्शन में गिरावट से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और पहचाने गए कारण क्या हैं;
- (ख) महाराष्ट्र से पिछले पांच वर्षों में वर्ष-वार और क्षेत्र - वार कितनी राशि का निर्यात हुआ;
- (ग) क्या महाराष्ट्र की निर्यात वृद्धि से मंदी पर कोई मूल्यांकन किया गया है और तत्संबंधी प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;
- (घ) नीति प्रोत्साहनों, संभारतंत्रों और पत्तन अवसंरचना, व्यापार सुविधा और बाजार विविधीकरण के माध्यम से राज्य में निर्यात-उन्मुख उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने प्रस्तावित हैं;
- (इ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के एमएसएमई, कृषि और विनिर्माण उत्पादों के लिए नए और उभरते वैश्विक बाजारों की पहचान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (च) पीएलआई योजना, जिलों को निर्यात केंद्र बनाने के कार्यक्रम, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क और व्यापार सुविधा केंद्रों के माध्यम से महाराष्ट्र की निर्यात परिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

- (क) इसके विपरीत, भारत ने वित वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (एच1) में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान पण्यवस्तु और सेवाओं, दोनों को मिलाकर कुल निर्यात 418.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.8% की वृद्धि दर्शाता है और एच1 निर्यात के लिए एक नया सर्वकालिक उच्च स्तर स्थापित करता है। उल्लेखनीय रूप से, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, क्यू1 (अप्रैल-जून 2025) और क्यू 2 (जुलाई-सितंबर 2025) दोनों ने अपनी-अपनी तिमाहियों के लिए अब तक के उच्चतम निर्यात स्तर दर्ज किए।

भारत का समग्र संचयी निर्यात निष्पादन मजबूत बना हुआ है। अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान कुल निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 4.1% बढ़कर 488 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पण्यवस्तु निर्यात 0.5% बढ़कर 253.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि इसी अवधि में सेवा निर्यात 8.2% बढ़कर 234.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

इसके अलावा, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद कई प्रमुख क्षेत्र मजबूत विस्तार दर्ज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला रहा, जिसमें 37.8% की तेजी से बढ़ोतरी हुई। कृषि-संबंधित श्रम-प्रधान श्रेणियों में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई – काजू (28.3%), अन्य अनाज (25.5%), मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद (24.0%), चाय (15.2%), कॉफी (12.3%), फल और सब्जियाँ (6.2%), चावल (5.5%), और अनाज से बने उत्पाद (3.9%)। समुद्री उत्पादों के निर्यात में 16.2% की वृद्धि हुई, अभ्रक और अन्य अयस्कों सहित खनिज निर्यात में 11.9% की वृद्धि हुई, जबकि दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स में 4.7% की वृद्धि हुई। भारत के सबसे बड़े निर्यात खंड, इंजीनियरिंग सामान, में 1.7% की स्थिर वृद्धि दर्ज की गई। इसी दौरान, पेट्रोलियम, वस्त्र, प्लास्टिक आदि जैसी कुछ प्रमुख श्रेणियों में बाहरी बाजार स्थितियों के कारण गिरावट देखी गई।

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के निर्यात का मूल्य नीचे दिया गया है। वर्ष-वार और क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (केवल अप्रैल - सितंबर 2025)
मूल्य करोड़ रुपये में	545083.65	581439.42	556400.42	557270.67	144281.16

स्रोत :डीजीआईसीएस और महाराष्ट्र सरकार

(ग) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 18 अगस्त 2025 को श्री अपूर्व चंद्रा (सेवानिवृत्त आईएएस) की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय कार्य बल समिति का गठन किया है। इस समिति का कार्य महाराष्ट्र के निर्यात क्षेत्रों पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव का आकलन करना, शमन रणनीतियों का प्रस्ताव करना और तत्काल राहत उपायों और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता पहलों की सिफारिश करना है। महाराष्ट्र राज्य के सभी प्रभागों में 10 से 26 सितंबर 2025 के बीच हितधारक परामर्श हुए।

(घ) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में निर्यातोन्मुखी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, महाराष्ट्र राज्य निर्यात संवर्धन नीति 2023 शुरू की गई है। इस नीति का उद्देश्य वित्त वर्ष 2027-28 तक महाराष्ट्र के निर्यात को दोगुना करके 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना और एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करना है। यह नीति एमएसएमई और क्षेत्र-विशिष्ट समूहों के लिए विशेष सहायता के साथ, नीतिगत प्रोत्साहनों, अवसंरचना के विकास, व्यापार सुगमता और बाजार विविधीकरण के माध्यम से एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर केंद्रित है।

नीतिगत प्रोत्साहन: यह नीति निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपये और औद्योगिक पार्कों के लिए 100 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एमएसएमई को ब्याज सब्सिडी, ईसीजीसी प्रीमियम रिफंड और लॉजिस्टिक्स सहायता के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है।

लॉजिस्टिक्स और व्यापार सुविधा: कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए, यह नीति बंदरगाहों और हवाई अड्डों के पास निर्यात-उन्मुख औद्योगिक पार्कों (ईओआईपी) को बढ़ावा देती है, जिससे बेहतर फस्ट माइल और लास्ट माइल संपर्क सुनिश्चित होते हैं। त्वरित अनुमोदन और निर्यात क्लीयरेंस के लिए एक डिजिटल सिंगल-विंडो प्रणाली के साथ-साथ समर्पित भंडारण और परिवहन सुविधाओं की योजना बनाई गई है।

बाजार विविधीकरण और संवर्धन: नीति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी के लिए समर्थन, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और जीआई-टैग उत्पादों को बढ़ावा देने और नए गंतव्यों की पहचान करने के लिए बाजार आसूचना प्रदान करने के माध्यम से वैश्विक पहुँच का विस्तार करने पर जोर देती है।

- (अ) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य निर्यात संवर्धन नीति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी के लिए सहायता, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और जीआई-टैग उत्पादों को बढ़ावा देने और नए गंतव्यों की पहचान करने के लिए बाजार आसूचना प्रदान करने के माध्यम से वैश्विक बाजार का विस्तार करने पर जोर देती है।
- (ब) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, निर्यात परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

निर्यात केंद्र के रूप में जिले: ओडीओपी के अंतर्गत जिला-विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देना, जीआई-टैग वाले सामानों की पहचान और एक तालुका दस निर्यातक (ओटीटीई) जैसी पहलें। इसके अलावा, जिलों में निर्यात सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं, जिला निर्यात संवर्धन परिषद (डीईपीसी) की बैठकें नियमित रूप से होती हैं, और बाधाओं को दूर करने तथा बाजार पहुँच को बढ़ावा देने के लिए जिला निर्यात कार्य योजनाएँ तैयार की जाती हैं।

निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क: महाराष्ट्र राज्य निर्यात संवर्धन नीति 2023 आधुनिक अवसंरचना, भंडारण, परीक्षण प्रयोगशालाओं और रसद समर्थन के साथ बंदरगाहों और हवाई अड्डों के पास निर्यात-उन्मुख औद्योगिक पार्कों (ईओआईपी) के विकास को बढ़ावा देती है।

व्यापार सुविधा केंद्र: महाराष्ट्र राज्य निर्यात संवर्धन नीति के अंतर्गत, माननीय मंत्री जी (उद्योग) की अध्यक्षता में महाराष्ट्र निर्यात संवर्धन परिषद (एमपीईसी) का गठन किया गया है। इस परिषद में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों

के सदस्य शामिल हैं और वे नीति में किसी भी संशोधन, सुझाव, परिवर्धन का सुझाव देते हैं और नीति की समीक्षा भी करते हैं।

दिनांक 09.12.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1410 के भाग (ख) के उत्तर से संबंधित अनुलग्नक

महाराष्ट्र का पांच वर्षों का क्षेत्र-वार निर्यात (मूल्य लाख करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (अप्रैल-सितंबर)
1	कृषि और खाद्य प्रसंस्करण	30545.25	38931.43	19917.64	22005.74	12549.03
2	कृषि, बागवानी और संबद्ध उत्पाद	23609.64	28419.56	29770.38	33260.85	15089.75
3	रसायन	50475.28	56361.22	56152.41	58252.08	30467.74
4	कॉर्क और कॉर्क से बनी चीज़ें	0.63	0.81	0.97	0.99	0.2
5	इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत घटक	69776.66	86115.34	96269.56	107436.25	59773.4
6	इंजीनियरिंग	56689.21	62006.06	63346.29	61214.46	38863.92
7	मत्स्य पालन और समुद्री उत्पाद	4046.51	4428.13	3742.56	3623.71	1868.95
8	जूते	712.28	759.42	712.21	627.73	141.62
9	रत्न और आभूषण	151954.18	153104.73	127076.31	115843.26	55467.86
10	ग्लास और ग्लासवेयर इंडस्ट्री	1815.29	2066.48	2133.07	2331.57	1170.19
11	हस्तशिल्प	578.59	549.72	2658.57	826.66	286.02
12	होम डेकॉर	1388.82	1657.5	1900.44	2030.93	1167.86
13	लोहा और इस्पात	27078.55	21743.53	25314.67	17315.28	8902.43
14	चमड़ा	490.01	730.26	721.79	702.36	376.12

15	धातु के बर्टन	22912.64	27805.5	26281.85	27406.23	14434.42
16	खनिज उत्पाद	112.02	259.52	184.98	190.4	124.41
17	विविध निर्मित आर्टिकल्स	880.22	1089.6	931.89	1050.69	567.63
18	कागज और पेपरबोर्ड	4353.17	4326.14	3757.3	4239.66	1997.06
19	पेट्रोलियम	12392.29	12741.82	11582.74	10838.35	6700.84
20	फार्मास्युटिकल	26830.09	28040.83	32009.16	34578.44	21347.15
21	प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पाद	11654.12	11145.87	11454.58	12235.19	6311.94
22	मुद्रण उद्योग के उत्पाद	557.42	683.29	759.19	815.49	450.07
23	परियोजना आयात	34.46	58.92	93.24	49.44	18.06
24	रबड़	6884.06	6838.88	6997.42	7311.95	3884.05
25	खेल और खिलौने	829.86	725.94	760.78	857.69	457.98
26	अस्थायी लेजिस्लेशन	0.36	0.36	1.26	0.83	0.42
27	कपड़ा और परिधान	38482.04	30848.56	31869.15	32224.46	14744.12
सकल योग		5,45,083.65	5,81,439.42	5,56,400.42	5,57,270.67	2,97,163.24

स्रोत: डीजीआईसीएस और महाराष्ट्र सरकार